दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, शुक्रवार 09 जुलाई 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-03, अंक- 279

महत्वपूर्ण एवं खास

सुप्रीम कोर्ट ने सूचना आयुक्तों की भर्ती पर केंद्र व राज्यों से मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को चार हफ्ते के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग व राज्य सूचना अयोगों में सूचना आयुक्तों की भर्ती की स्थिति बताने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने केंद्र व राज्यों से सूचना आयुक्तों की भर्ती संबंधी वर्ष 2019 के आदेश के अनुपालन के बारे में भी रिपोर्ट तलब की है। जस्टिस एस. अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने पाया कि एक वर्ष पहले केंद्र सरकार ने आखिरी स्थिति रिपोर्ट दाखिल की थी। लिहाजा पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान को फिर से स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर नियुक्तियों की वर्तमान स्थिति और भर्ती के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया। वर्ष 2019 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सूचना आयुक्तों का पद रिक्त होने के दो महीने पहले से ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। साथ ही सर्च कमेटी को नौकरशाहों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के नामचीन लोगों को भी सूचना आयुक्त नियुक्त करने पर विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई कर रही है। अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

देश में नए कोरोना मामलों ने मात देने वालों की संख्या को पछाड़ा

एक दिन में 45,892 नए मामले, 44,291 लोग हुए ठीक

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। मसलन कोरोना वायरस के मामलों में बीते करीब दो महीने से लगातार जारी गिरावट अब कम होती दिख रही है। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना संक्रमण के 45,892 नए केस मिले हैं। वहीं इस अवधि में 44,291 लोग रिकवर हुए हैं। पिछले 55 दिनों के बाद यह पहला मौका है, जब कोरोना के नए मामलों की संख्या रिकवर होने वाले लोगों से अधिक है। यही नहीं पिछले एक दिन में कोरोना के चलते 817 लोगों की मौत हुई है। यही नहीं बुधवार की तुलना में एक्टिव केसों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। तब 4.59 लाख एक्टिव केस देश भर में थे, जो अब बढ़कर 4.60 लाख के पार हो गए हैं। फिलहाल देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों की संख्या 4,60,704 है। देश में मिले अब तक कुल केसों के मुकाबले एक्टिव केसों की संख्या 1.50 फीसदी हैं। अब तक देश में 3.07 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 2.98 करोड़ लोगों ने वायरस को मात दी है। पिछले एक दिन में ही 44,291 लोग रिकवर हुए हैं। हालांकि ऐसा 55 दिन बाद हुआ है, जब रिकवर होने वालों की संख्या एक्टिव मामलों की तुलना में कम हुई है। यह चिंताओं को बढ़ाने वाली बात है। हालांकि अब भी कोरोना का रिकवरी रेट देश में 97.18 पर्सेंट बना हुआ है।

नहर में नहाने गए दो बच्चे देखते ही देखते तेज बहाव में समा गये

बाराबंकी (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले के जैदपुर इलाके में नहर में नहाने समय दो बच्चे देखते ही देखते पानी के तेज बहाव में समा गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार , जैदपुर क्षेत्र के पाटमऊ गांव निवासी मुश्तकीम अपने परिवार के सदस्यों के साथ बीती शाम गांव के निकट खेत में धान लगाने गया था। साथ में उनके बच्चे भी गए थे। उसी बीच मुश्तकीम का 06 वर्षीय बेटा फैसल और मुश्तकीम की बहन का बेटा अनमोल अन्य बच्चों के साथ खेत के पास ही खेलने लगा। खेत के निकट शारदा सहायक नहर की शाखा गुजरी है। उन्होंने बताया उमस भरी गर्मी से परेशान बच्चे खेलते-खेलते नहर पर चले गये और उसमें नहाने लगे। पानी के तेज बहाव के चलते फैसल गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसे डूबता देख अनमोल ने उसे बचाने का प्रयास किया , लेकिन वह भी बह गया और देखते ही देखते दोनों बच्चे गहरे पानी मे समा गए। बाकी दो बच्चे चिल्लाते हुए गांव में पहुंचे और घटना खबर दी । आनन-फानन परिजन नहर की ओर दौड़ पड़े और अपने बच्चों की तलाश करने लगे।सूचना पर पहुंची पुलिस ने नहर में जाल डलवाया और ग्रामीणों की मदद से बच्चों के शवों की तलाश शुरू की। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद काफी दूर अनमोल का शव बरामद हो सका जबकि दूसरे बच्चे की तलाश की जा रही है।

मोदी के ज्यादातर नए मंत्रियों ने संभाला कार्यभार

» पुराने मंत्रियों ने शुरू किया कामकाज

नई दिल्ली (आरएनएस)। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब जिन नए मंत्रियों को जिम्मेदारी मिली है, उन्होंने अपना कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है। बुधवार शाम को 40 से अधिक मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की, जबकि कई मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है तो कई मंत्रियों के विभाग बदले गए हैं। नए मंत्रियों ने गुरुवार सुबह से अपना कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है तो वहीं पुराने मंत्रियों ने अपना कामकाज भी शुरू कर दिया।

❑ **पीयूष गोयल व अनुप्रिया ने कार्यभार संभाला–** पीयूष गोयल ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। इसके अलावा उन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री एवं कपड़ा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अनुप्रिया सिंह पटेल ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे दूसरी बार ये मौका दिया। ये अच्छा विभाग है, मेरे लिए ये नया विभाग है मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वहीं निसिथ निसिथ प्रमाणिक ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री एवं युवा मामले और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार सांसद जॉन बारला ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया। ।

❑ **अनुराग ठाकुर व लेखी ने कार्यभार संभाला–** अनुराग सिंह ठाकुर ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री के साथ-साथ युवा मामले और खेल मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे यह जिम्मेदारी देने के लिए मैं पीएम मोदी का शुक्रगुजार हूं। संघों, महासंघों के समर्थन से, मैं भारतीय खेलों को आगे ले जाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। प्रमोशन पाने वाले अनुराग ठाकुर ने सूचना-प्रसारण मंत्रालय का काम संभाल लिया। अनुराग ने प्रकाश जावड़ेकर की जगह ली है। कामकाज संभालने के बाद ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले सात सालों में देश के विकास के लिए बहुत शानदार काम किया है। मैं सूचना-प्रसारण मंत्रालय में मुझसे पहले लोगों द्वारा किए गए काम को आगे बढ़ाऊंगा। साथ ही पीएम मोदी द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि मैं पीएम, गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इस पोर्टफोलियो को संभालने की जिम्मेदारी दी है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि मैं आज अपने विभाग में शामिल हो गया हूं। मैं पहले 10 दिनों तक अपने विभाग के कार्यों का पूरा अध्ययन करूंगा। 19 तारीख को फिर मैं पूरे विस्तार से अपने विभाग के कार्यों के बारे में जानकारी दूंगा।

❑ **रेलवे आगे ले जाएंगे अश्विनी वैष्णव–** देश के नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार सुबह मंत्रालय का कामकाज संभाला। उन्होंने पीयूष गोयल की जगह ली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रभार संभालते हुए कहा कि रेल क्षेत्र में पिछले 67 वर्षों में शानदार काम किया गया है। मैं यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के मुताबिक, इसे आगे ले जाने के लिए आया हूं। नव नियुक्त मंत्री ने बाद में ट्विटर पर प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आज केंद्रीय रेल मंत्री के तौर पर प्रभार संभाला।

❑ **पीएम की अपेक्षा पूरी करेंगे मांडविया–** नए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कामकाज संभालने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री की अपेक्षा के अनुरूप काम करने की कोशिश करूंगा। बता दें कि मंडाविया डॉ. हर्षवर्धन की जगह ली है।

❑ **किसानों के लिए करेंगे काम मुरुगन–** तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष एल मुरुगन ने गुरुवार को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालने के बाद मुरुगन ने कहा कि वह देश भर के किसानों के कल्याण के लिए काम करेंगे। मुरुगन मंत्रालय में अपने वरिष्ठ मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला की सहायता के लिए संजीव बाल्यान के साथ काम करेंगे।

❑ **रिजिजू ने संभाला कानून मंत्रालय –** नए कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने पदभार संभाला लिया। उन्होंने कहा कि हर मंत्रालय और हर पद की अपनी गरिमा होती है। प्रधानमंत्री ने मुझपर जो भरोसा जताया है, उस पर खरा उतरना मेरे सामने एक चुनौती है।

आगरा जेल में बंद नाबालिगो को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट में बृहस्पतिवार को 13 उन दोषियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है जिन्हें अपराध के वक्त नाबालिग घोषित किया जा चुका है। पिछले हफ्ते शीर्ष अदालत ने इस मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद ने कहा कि इस मामले के तथ्यों को जांच करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इन सभी को अंतरिम जमानत दी जा सकती है। जिसके बाद पीठ ने सभी 13 को अंतरिम जमानत पर छोड़ने का निर्णय लिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 13 उन दोषियों को तत्काल जेल से रिहा करने की मांग की गई है क्योंकि किशोर न्याय बोर्ड(जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड) के द्वारा अपराध के वक्त नाबालिग घोषित किया जा चुका है। ये सभी फिलहाल आगरा सेंट्रल जेल में बंद हैं और उन्हें खूंखार अपराधियों के साथ जेलों में रखा गया है।

अपराध के दौरान सभी बच्चे थे नाबालिग– वकील ऋषि मल्होत्रा के माध्यम से दायर इस याचिका में कहा गया था कि 2012 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किए जाने के बाद किशोर न्याय बोर्ड को कैदियों की किशोरावस्था से संबंधित आवेदनों का निपटारा करने के निर्देश दिए गए थे।

भारत-पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी पर शुरु हुई बातचीत

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत-पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर लगभग ढाई साल के बाद बातचीत फिर से शुरू हो गई। देखना यह होगा कि यह बातचीत दोनों देशों के रिश्तों में आई तना-तानी को कम कर पाती है या नहीं।

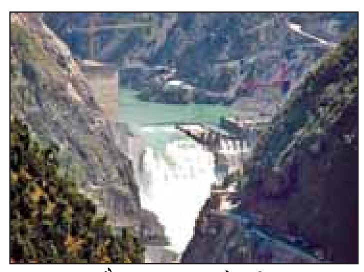

नदियों के पानी के बंटवारे के लिए बने स्थायी सिंधु आयोग (पीआईसी) की सालाना बैठक नई दिल्ली में शुरू हो चुकी है. दो दिन की वार्ता 24 मार्च तक चलेगी। आयोग की पिछली बैठक 29-30 अगस्त, 2018 को लाहौर में हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में की गई इंडस वाटर्स ट्रीटी के मुताबिक आयोग की बैठक हर साल कम से कम एक बार जरूर होनी चाहिए। एक बैठक भारत में, तो अगली पाकिस्तान में होनी चाहिए, लेकिन इस बार दो बैठकों के बीच का अंतराल ज्यादा लंबा हो गया है। 2019 में आयोग के पाकिस्तानी आयुक्त एक टीम ले कर चिनाब नदी के घाटी में निरीक्षण के लिए चले गए थे और 2020 में आयोग की बैठक कोरोना वायरस महामारी की वजह से नहीं हो पाई। 2021 की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारतीय सिंधु आयुक्त प्रदीप कुमार सक्सेना कर रहे हैं और पाकिस्तानी टीम का नेतृत्व वहां के सिंधु आयुक्त सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह कर रहे हैं। इस बैठक को दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने वाले एक कदम के रूप में भी देखा जा रहा है।

काफी दिनों तक रिश्ते रहे खराब- दरअसल पिछली बैठक के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी खराब हो गए थे. फरवरी 2019 में जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले और उसके 12 दिन बाद भारतीय वायु सेना द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई हमले की वजह से दोनों देश जंग की कगार पर पहुंच गए थे। लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद अब जा कर हालात में कुछ सकारात्मक बदलाव नजर आ रहे हैं।

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सोनिया समेत कई अन्य नेताओं ने वीरभद्र के निधन पर जताया शोक

नई दिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्य नेताओं ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन पर बृहस्पतिवार को दुख जताया और राज्य के विकास में उनके योगदान को याद किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह का लंबी बीमारी के बाद बृहस्पतिवार तड़के निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे।

उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए राष्टपति कोविंद ने ट्वीट किया कि वीरभद्र सिंह के निधन की खबर सुन कर दुखी हूं। छह दशक के उनके राजनीतिक करियर में मुख्यमंत्री और सांसद के तौर पर उनकी भूमिकाएं हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जाहिर करती हैं। परिवार एवं समर्थकों के प्रति संवेदनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सिंह ने राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा लोगों की सेवा की। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वीरभद्र सिंह का लंबा राजनीतिक जीवन रहा जो प्रशासनिक और विधायी अनुभवों से भरा हुआ था। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लोगों की सेवा की। उनके निधन से दुखी हूं। परिवार के सदस्यों और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं।पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वीरभद्र की पत्नी प्रतिभा सिंह को पत्र लिखकर कहा कि उनके जाने से कांग्रेस में बड़ा शून्य पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि वह देश में कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक थे। उन्होंने नौ विधानसभा और पांच लोकसभा के चुनाव जीते। वह छह बार मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में भी मंत्री रहे। राज परिवार से होने के बावजूद उनकी सबसे बड़ी ताकत जनता के साथ उनका जुड़ाव था। उनके निधन से देश ने एक जन नेता और कुशल प्रशासक खो दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने वीरभद्र के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को चिर शांति प्रदान करें। मैं उनके परिजनों व समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।''

सोनिया ने कहा कि छह बार मुख्यमंत्री पद पर और पूर्व केंद्रीय मंत्री के तौर पर सेवाएं दे चुके वीरभद्र सिंह को विभिन्न पीढ़ियों में कई कद्दवार नेताओं के साथ काम करने का का मौका मिला।

मंडियों के जरिए किसानों तक पहुंचेंगे एक लाख करोड़ रुपये

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही इस बैठक में किसानों को फायदा पहुंचाने का फैसला किया गया। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि कैबिनेट ने फैसला लिया है कि मंडियों के जरिए किसानों तक एक लाख करोड़ रुपये पहुंचाए जाएंगे।

नड्डा ने नवनियुक्त मंत्रियों के साथ की बैठक– भाजपा के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए नए सदस्यों के साथ गुरुवार को अपने आवास पर बैठक की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में भाजपा के संगठन महामंत्री बी एल संतोष और पार्टी महासचिव व केंद्रीय श्रम मंत्री सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे।

मोदी सरकार के ये नए 15 कैबिनेट मंत्री- नारायण तनु राणे, सर्बानंद सोनोवाल, डॉ. वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामचंद्र प्रसाद सिंह, किरण रिजिजू, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मांडविया, भूपेंद्र यादव, पशुपति पारस, जी किशन रेड्डी, पुरुषोत्तम रूपाला, अनुराग सिंह ठाकुर, अश्विनी वैष्णव।

फेसबुक को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका : वाइस प्रेसिडेंट को जारी किए गए समन पर रोक लगाने से किया इनकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। फेसबुक को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने दिल्ली दंगे को लेकर दिल्ली विधानसभा के पैनल की तरफ से फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट को जारी किए गए समन पर रोक लगाने से इनकार किया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बेहद तल्ख टिप्पणियां भी की। कोर्ट ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स रेलवे प्लेटफॉर्म्स की तरह नहीं हैं जहां ट्रेनों की आवाजाही नियंत्रित होती है। सोशल मीडिया के जरिए छेड़छाड़ से आज लोकतांत्रिक बुनियाद को खतरा होता दिख रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुनियाभर में स्थापित स्वतंत्र लोकतंत्रों में इस तरह का असर देखा जा रहा है और वो चिंतित हैं। चुनाव और वोटिंग प्रक्रिया जो लोकतांत्रिक सरकार की बुनियाद होती हैं, उनके लिए सोशल मीडिया तिकड़मों से खतरा बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तकनीकी युग ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पैदा किए हैं- ये रेलवे प्लेटफॉर्म्स की तरह नहीं हैं जहां ट्रेनों का आना-जाना नियंत्रित होता है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स किसी समय पूरी तरह अनियंत्रित हो सकते हैं, इनकी अपनी चुनौतियां हैं।

सोशल मीडिया की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए

सोशल मीडिया की ताकत का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके मार्च 2021 तक 2.85 अरब मंथली ऐक्टिव यूजर्स हैं। यह दुनिया की कुल आबादी के एक तिहाई से ज्यादा है। कोर्ट ने कहा, अगर राष्ट्रीय संदर्भ में देखें तो भारत में फेसबुक सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके करीब 27 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। इतने बड़ी ताकत के साथ जिम्मेदारी जरूर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि फेसबुक ने लोगों को आवाज उठाने और अभिव्यक्ति की आजादी देने में अहम भूमिका निभाई है। इस पर राज्य का पहरा नहीं होना चाहिए लेकिन इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि इसी प्लेटफॉर्म से विध्वंसकारी संदेश, आवाज और विचारधारा भी उभर रही है।

यह है पूरा मामला

दरअसल, फरवरी 2020 के दिल्ली दंगे के मामले में दिल्ली विधानसभा की शांति एवं सौहार्द समिति ने फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और एमडी अजीत मोहन को समन भेजा है। समिति ने पिछले साल 10 और 18 सितंबर को मोहन को समन भेज उन्हें अपने सामने पेश होने को कहा है। समिति ने यह समन दंगे के दौरान कथित भड़काऊ भाषणों के फैलने में उसकी भूमिका की जांच के सिलसिले में भेजा है। फेसबुक ने समन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। उसी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणियां कीं और याचिका को रद्द कर दिया। हालांकि, पिछले साल 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक को राहत देते हुए दिल्ली विधानसभा की समिति को उसके खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था।